

परिशिष्ट-“अ”

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-589 प्रश्नांश “क” से संबंधित जानकारी

- जिला धार-जिला धार अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के परिपत्र अनुसार जी.एस.टी. फॉर्म-7 में जानकारी राहित प्राप्त कटौती की राशि ऑनलाइन जमा की गयी है। विवरण इस प्रकार है:-

GSTIN of the Deductee	Trade Name	Amount paid to the Deductee on which tax is deducted	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Date Of Deposit
1	2	3	4	5	6	7
23APFPJ3541R1ZN	Mamaji Tcht House Dhar	624944	0	6250	6250	17.07.2020
23BIBPS1152R2Z8	Yesh Solutions	361864	0	3619	3619	17.07.2020
23AIRPC173611ZM	Tulsi Construction Company	4558989	0	45590	45590	10.03.2021
		3139400	0	31394	31394	10.03.2021
23AABCE9378F5ZG	Volve Eicher Commercial VE	1740302	0	17403	17403	10.07.2021

- जिला बैतूल-जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में राशि 2.50 लाख से अधिक की सामग्री क्रय नहीं किये जाने के कारण जी.एस.टी. फॉर्म-7 जमा नहीं किया गया है।
- जिला विदिशा-जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में राशि 2.50 लाख से अधिक की सामग्री क्रय नहीं किये जाने के कारण जी.एस.टी. फॉर्म-7 जमा नहीं किया गया है।
- जिला रायसेन-जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में राशि 2.50 लाख से अधिक की सामग्री क्रय नहीं किये जाने के कारण जी.एस.टी. फॉर्म-7 जमा नहीं किया गया है।

31/7/2021
 संयुक्त संचालक(वित्त)
 पंचायत राज संचालनालय
 भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

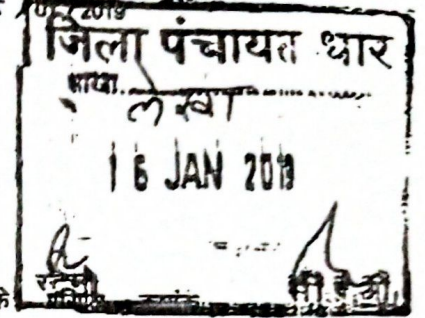
परिशिष्ट ६

क्रमांक / 28/पंचायति/2019/
प्रति,

दिनांक

15/01/2019

मुख्य कार्यवाहन अधिकारी,
जिला पंचायत -समस्त
मध्यप्रदेश।



विषय: जीएसटी अंतर्गत स्रोत पर कर का कटौती।

- भारत सरकार के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के 65/39/2018-DOA दिनांक 14.09.2018 एवं मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, के परिपत्र क्रमांक 488/1947/1/पांच दिनांक 22.08.2017 (संलग्न) द्वारा जीएसटी के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती के निर्देश एवं स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसिजर (SOP) जारी किये हैं। अप्रजोक्त डीलर/सेवा प्रदायकता (पुनर्गठन की राशि चाहे जितनी हो) द्वारा माल या सेवा या दोनों की दी गई सप्लाय पर कर कटौती नहीं किया जाना है।
- यदि ग्राम पंचायत/जनपद/जिला पंचायत के द्वारा किसी भी एक अनुबंध के अंतर्गत रुपये 2.50 लाख से अधिक के कर योग्य माल अथवा सेवाओं (या दोनों) की आपूर्ति जीएसटी में पंजीकृत एक सप्लायर से ली जा रही है तो उस निकाय को जीएसटी में डिटेक्टर पंजीकृत प्राप्त करना होगा। पूरी तरह से पंजीकृत सप्लायर से माल या सेवा लेने पर डिटेक्टर पंजीकृत की आवश्यकता नहीं है और स्रोत पर कटौती की आवश्यकता भी नहीं है।
- निकायों को स्रोत पर कर कटौती करने हेतु जीएसटी पोर्टल पर और सचिव/सहायक सचिव द्वारा PAN, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल के माध्यम से पंजीकृत करना होगा।
- यदि किसी भी अनुबंध अंतर्गत सप्लायर से प्राप्त की गई कर योग्य माल या सेवा (या दोनों) की कीमत (जीएसटी को छोड़कर) रुपये 2.50 लाख से अधिक है, तो राज्य के भीतर से सप्लाय होने पर निर्धारित 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत स्टैंड जीएसटी एवं 1 प्रतिशत सेन्ट्रल जीएसटी) का कटौती किया जाना है। अंतर्राज्यीय सप्लाय प्राप्त होने पर केवल 2 प्रतिशत आईजीएसटी का कटौती होगा। दिनांक 01.10.2018 के पूर्व जारी टेक्स इनवाइस पर कटौती नहीं करना है।
- ऐसे मामलों में आंशिक या पूर्ण मुगठान करने पर CGST (TDS) कटौती किया जाना होगा। स्रोत पर किये गये कर के कटौती को अगले माह की 10 तारीख तक शासन को जमा कराना तथा फॉर्म-जीएसटीआर-7 में आनलाईन रिटर्न करना अनिवार्य है। (साथ ही कॉमन पोर्टल (<https://www.gst.gov.in>) के द्वारा जिस व्यक्ति से कटौती किया गया है, उसको सिस्टम के द्वारा जनरेटेड फॉर्म-जीएसटीआर-7A में कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।) डिटेक्टर द्वारा निर्धारित समय सीमा में फॉर्म-जीएसटीआर-7 में विवरण पत्र प्रस्तुत न करने पर रुपये 100/- प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 5000/-) पित्त शुल्क CGST

16 JAN 2019

एव SGST के अधीन पृथक-पृथक देय होगा। फॉर्म-जीएसटीआर-7ए में प्रमाण पत्र राख्यावधि में नहीं दिए जाने पर रुपये 100/- प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 5000/-) विलंब शुल्क CGST एवं SGST के अधीन पृथक-पृथक देय होगा। डिडक्टर द्वारा टीडीएस नहीं करने, कम टीडीएस करने एवं टीडीएस की गई जितनी राशि नहीं काटी गई है या कम राशि काटी गई या नहीं जमा हुई राशि या रु. 10000/- जो अधिक हो, की शास्ति के प्रावधान है। जीएसटी के अंतर्गत स्रोत पर टीडीएस कटौती करने के संबंध में विस्तृत निर्देश उगलब्य है, जिसमें माल और सेवा को परिभाषित किया गया है तथा टेक्स कटौती करने के संबंध में उदाहरण भी दिये गये हैं। यथा में टेक्स कटौती से संबंधित विभिन्न सामान्य प्रश्न, उत्तर (FAQ) भी दिये गये हैं।

पंच-परमेश्वर पोर्टल पर स्रोत पर जीएसटी कटौती का प्रावधान किया जा रहा है ताकि कटौती की राशि तत्काल शासन को जमा कराने की सुविधा हो। जब तक पंचपरमेश्वर पोर्टल पर उक्त व्यवस्था नहीं होती है तब तक भुगतानकर्ता को जी.एस.टी. का कटौती कर राशि का भुगतान किया जावे तथा जी.एस.टी की राशि जी.एस.टी. विभाग में जमा की जावे।

उक्त व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिस हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न: 1. परिपत्र क्रमांक 65/39/2018-DOR दिनांक 14.09.2018

2. परिपत्र क्रमांक 483/1947/1/पांच दिनांक 22.08.2017

3. स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसिजर (SOP)

(अमित राठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 15/01/2019

पृ. क्रमांक / 2 / पंचावधि / 2019 /

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय आयुक्त समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त, जनपद पंचायत की ओर सूचनार्थ।

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग